Zero Action Only Pollution

अब नहीं तो
कब करोगे?

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ

चार्जशीट

- लोक अभियान -

प्रस्तावना

आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण के नाम पर अब तक सिर्फ ये किया–

- बयानबाजी
- बैठकें
- बेतुकी बातें

आम आदमी पार्टी ने हर मोर्च पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। उसे डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं की। दिल्ली को गैस चैंबर बनाकर दिल्लीवासियों को प्रदूषण, घुटन और बीमारियों के बीच छोड़ दिया। आज दिल्ली का बच्चे से लेकर बूढ़े तक कई सिगरेटों के बराबर और उससे भी खतरनाक धुआं पीने के लिये मजबूर है।

दिल्ली कोई आना नहीं चाहता

दिल्ली सरकार की नाकामी का असर गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास के दूसरे क्षेत्रों से रोज नौकरी और व्यापार के लिये आने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। जानलेवा स्तर पर जा पहुंचे प्रदूषण के कारण दिल्ली की छवि देश ही नहीं, विदेशों मे भी एक जहरीली हवा वाले शहर की बन चुकी है। चाहे नौकरी हो, पर्यटन हो, पढ़ाई हो, इलाज हो या कुछ और, लोग इसके लिये दिल्ली आने से बचने लगे हैं। विदेशी मेहमान और राजनायिक तक सोच में हैं।

प्रदूषण का राजनीतिकरण

लेकिन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण जैसे गंभीर मामले का राजनीतिकरण कर दिया। सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति से विकास के काम नहीं होते। जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार ने 'सबका साथ–सबका विकास' के मंत्र के साथ चलने वाली केंद्र सरकार के साथ सत्ता संभालते ही असहयोग और आरोप की राजनीति शुरु कर दी।

केवल ट्विटर–फेसबुक की राजनीति

धरना और प्रदर्शन में माहिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण पर केवल ट्विटर और फेसबुक पर अपडेट किए गए, मीडिया में बयान जारी किये और कोर्ट के चक्कर लगाए। लेकिन इससे आगे वह कुछ नहीं कर पाई।

जनता से झूठे वादे कर सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार तीन साल से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसलिए इस आरोप–पत्र को जारी किया जा रहा है। आरोप पत्र में केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं बताई गई है बल्कि प्रदूषण के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी सुझाव हैं।

विजय गोयल

विजय गोयल
अध्यक्ष
लोक अभियान

आरोप नं. 1. – जरूरत थी 11000 बसों की, सड़कों पर हैं सिर्फ 4000

- हाईकोर्ट के 11,000 बसें खरीदने के आदेश पर 10 साल बाद भी अमल नहीं
- 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध पूरी तरह विफल
- मुख्यमंत्री जी की 400 इलेक्ट्रिक बसें लापता

➡ प्रदूषण को कम करने के लिये हमेशा ये जरूरी होता है कि हम हवा में पेट्रोल, डीजल इत्यादि से होने वाले प्रदूषण को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करके कम करने की कोशिश करें। दिल्ली सरकार न ही बसों की संख्या बढ़ा पाई है, और न ही Delhi Integrated Multi Model Transport System (DIMTS) को सही ढंग से लागू कर पाई है। जाहिर है कि जनता परिवहन के लिये निजी वाहनों को इस्तेमाल करने पर विवश है जिससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। दिल्ली सरकार ने 2000 बसें खरीदने के अपने इरादे को यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल में दिया कि उसके पास इन बसों को खड़ी करने की जगह नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथारिटी (EPCA) ने मई 2016 में डीडीए और दूसरी एजेंसियों की मदद से 2000 बसों की पार्किंग चिन्हित कर दिल्ली सरकार को जानकारी दी थी।

उपायः जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में सार्वजनिक वाहनों को खास दिवसों पर मुफ्त दिया गया और कार पूलिंग को बढ़ावा दिया गया है। जर्मनी में सार्वजनिक परिवहन बेहतर किया गया है और ट्राम नेटवर्क को बढ़ावा दिया गया है। इसी तरह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को युद्ध स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है।

आरोप नं. 2– सड़कों पर उड़ती धूल, आराम से सोती दिल्ली सरकार

- सड़कों की धूल खींचने वाले वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदे गए
- पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं
- दिल्ली का 50 प्रतिशत प्रदूषण सिर्फ सड़कों की धूल के कारण

यह जगजाहिर है कि सड़कों पर उड़ती धूल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के फेफड़ों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। यह जानते हुए भी कि दिल्ली में Air Quality Index (AQI) 500 से भी अधिक के जानलेवा स्तर पर जा चुका है, दिल्ली सरकार चादर ओढ़कर सोती रही, जबकि दिल्ली जहरीली हवा की चादर में लिपटती रही। बच्चों के लिये स्कूल तब बंद हुए जब उनके माता–पिता ने गुहार लगाई। दोबारा स्कूल खोलते वक्त भी कोई एहतियाती उपाय नहीं किये गए।

उपायः यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि जब सड़कों पर धूल उड़ती है तो उसे या तो खींचा जाना चाहिए या पानी के छिड़काव के द्वारा बिठाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार सामान्य ज्ञान की परीक्षा में भी फेल निकली। साल 2014 में चीन के कई शहरों में धुंध छा गई थी। इससे निपटने के लिये यहां मल्टी–फंक्शन डस्ट सेप्रेशन ट्रक का इस्तेमाल किया गया. इसके ऊपर एक विशाल वॉटर कैनन लगा होता है जिससे 200 फीट ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि धूल नीचे बैठ जाए। दिल्ली में भी उच्च क्षमता वाले वैक्यूम क्लीनर और स्प्रिंकलर्स को तुरंत इस्तेमाल करने की जरूरत है।

आरोप नं. 3– बेलगाम औद्योगिक प्रदूषण और अनाधिकृत निर्माण का बढ़ता कारोबार

- धुंए के बादल बनाती औद्योगिक चिमनियों और निर्माण कार्यों पर रोक नहीं
- अनाधिकृत फैक्टरियों, वेयर हाउस और भवन निर्माण की निगरानी और रोकथाम का कोई सिस्टम नहीं
- फैक्टरी चलाने की लाइसेंस प्रक्रिया भी लचर
- औद्योगिक गतिविधियां दिल्ली के प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसका योगदान दिल्ली के प्रदूषण में 23 प्रतिशत है।

दिल्ली में बेहिसाब अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहा है जिसे दिल्ली सरकार लगातार नजरअंदाज करती आई है। आईआईटी कानपुर द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि दिल्ली में उद्योग इत्यादि सल्फर डाइ ऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का सबसे बड़ा स्रोत है जिनसे सांस की बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। यह रिपोर्ट जारी हुए एक साल बीत चुका है पर दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञ संस्थान की इस रिपोर्ट का अध्ययन करना और उस पर अमल करना उचित नहीं समझा।

उपायः दिल्ली की औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रण के मानक तय होने चाहिए और इसका पूर्ण पालन सुनिश्चित होना चाहिए। एनजीटी के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण नियंत्रण के निर्देशों का पालन और निगरानी सख्त तरीके से होनी चाहिए। अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिये अफसरों की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए और काम ठीक से न करने पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लघु तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों का सर्वे होना चाहिए और अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयां बंद होनी चाहिए।

आरोप नं. 4– ऑड–ईवन का नाटक बार–बार

- यह केवल एक पब्लिसिटी स्टंट–100 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिसिटी में बहाए
- 60 प्रतिशत से अधिक वाहनों को किसी न किसी कारण से ऑड–इवन से छूट दी गई जिससे इसका उद्देश्य विफल
- इस बार ऑड–इवन का निर्णय प्रदूषण स्तर के जानलेवा हो जाने के बाद लिया गया जबकि पूरी दिल्ली कई दिन पहले से जहरीली हवा में सांस ले रही थी
- पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की व्यवस्था किये बिना ऑड–इवन का फैसला बचकाना

अपने वादे के मुताबिक 2000 बसों की व्यवस्था किये बिना दिल्ली पर तीसरी बार ऑड–इवन थोपने की कोशिश एक अमानवीय फैसला था। दिल्ली में प्राइवेट बसें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सरकारी बसें 5121 से घटकर 3944 हो गईं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों पर ग्रीन टैक्स लगाकर 829 रुपए जुटाए लेकिन इसमें से सिर्फ 93 लाख खर्च किये। जनता से टेक्स लेकर भी सरकार ने परिवहन और प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं किया। सवारियों के बोझ से हांफतीं DTC बसों को ऑड–ईवन के दौरान मुफ्त चलाने से कुछ हासिल नहीं होता। एनजीटी की फटकार ने साबित कर दिया कि केजरीवाल सरकार के पास प्रदूषण की समस्या के नाम पर एक ही अधकचरा उपाय है– ऑड–इवन।

उपायः ऑड–इवन को लागू करने से पहले पर्याप्त सरकारी बसें होनी चाहिए। ई बसों की संख्या भी पर्याप्त हो। कार पूलिंग करने वालों के लिये सुविधाएं बढ़ाई जाएं। केंद्र से बात करके मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएं।

आरोप नं. 5– पराली के मामले में भी केजरीवाल लाचार

- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हर साल जलने वाली पराली को लेकर समय रहते कोई बातचीत नहीं
- दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली के किसानों की पराली की समस्या पर कोई कदम नहीं
- दो तिहाई पराली जल जाने के बाद पड़ौसी राज्यों के साथ बैठक की औपचारिकता

पड़ौसी राज्यों में हर साल अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पराली जलाई जाती है। अब तक 3.4 करोड़ टन में से करीब 2.5 करोड़ टन पराली जलाई जा चुकी है। इस समस्या के लिये समय रहते पड़ौसी राज्यों से बात करके कारगर कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन 7–8 नवंबर तक हालात भयावह होने का इंतजार किया गया।

उपायः केंद्र और पड़ौसी राज्यों से बात करके किसानों को पराली जलाने के विकल्प दिए जा सकते हैं। पराली का इस्तेमान ईंट और खाद आदि बनाने में किया जा सकता है। किसानों को मक्के जैसी दूसरी फसलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

आरोप नं. 6– बेलगाम और विस्फोटक होते कचरे के पहाड़

- दिल्ली की भलस्वा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट के बारे में कोई कदम नहीं उठाया
- कचरे की प्रोसेसिंग के बारे में कोई पहल नहीं
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने और उसको प्रभावी तरीके से लागू करने की कोई सोच नहीं

कचरे के पहाड़ दिल्ली की नई पहचान बनते जा रहे हैं। इससे न केवल बदबू, प्रदूषण और जानमाल का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में गाजीपुर लैंडफिल साइट में विस्फोट के बाद कचरा सड़क पर आने से दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी दिनों से ये चर्चा रही है कि दिल्ली में 13,000 टन कचरा रोज इकट्ठा होता है लेकिन उस हिसाब से लैंडफिल और डंपिंग साइट्स काफी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जो भी साइट्स मौजूद हैं, वहां से भी कूड़े का ट्रीटमेंट और रिसाइक्लिंग ठीक तरह से नहीं हो रही है।

उपायः कूड़े के कलेक्शन के बाद ही इसे छोटे–छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स या कम्पोस्ट में इस्तेमाल किया जाए तो यह ऊर्जा का आसान और सस्ता स्रोत बन सकता है। साथ ही बदबू और प्रदूषण का भी इलाज हो जाएगा। अगर हम लोगों में आर्गेनिक और नॉन आर्गेनिक कचरे को अलग करने के लिये जागरुक करें तो प्राथमिक स्तर पर ही कचरे के सही इस्तेमाल की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी जो बाद में बहुत मेहनत से की जाती है।

दिल्ली में आखिर प्रदूषण क्यों–

सड़कों की धूल (Road Dust)	50%
औद्योगिक प्रदूषण (Industrial Pollution)	23%
स्थानीय धूल (Local Dust)	20%
वाहनों का धुंआ (Vehicular Emission)	7%

आरोप नं. 7– यमुना की सफाई का बंटाधार

- 22 किलोमीटर के सफर में यमुना में मिलते हैं 18 नाले
- बिना ट्रीटमेंट वाला औद्योगिक कचरा और रासायनिक प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती
- दिल्ली की यमुना में ऑक्सीजन है ही नहीं
- यमुना की सफाई की बजाए यमुना आरती का नाटक
- यमुना में अमोनिया की मात्रा शून्य की बजाए 1.12 पार्टिकल्स पर मिलियन (PPM) तक पहुंची

भगवान श्री कृष्ण की प्रिय यमुना आज पूरी तरह से गंदे नाले में बदल चुकी है। रोज यमुना में 3296 मिलियन गैलन लीटर अपशिष्ट और गंदा पानी गिर रहा है। एनजीटी ने छोटे नालों के गंदे पानी के शोधन के लिये 14 सीवरेज शोधन संयंत्र लगाने के आदेश दिये थे। इस साल यह योजना पूरी होनी थी लेकिन यह शुरू भी नहीं हो पाई। जल दिल्ली सरकार के जल बोर्ड विभाग के सीवरेज शोधन संयंत्रों की क्षमता भी जरूरत से 150 Millions of Gallons Per Day (MGD) कम है। यही नहीं, 50 प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में सीवर लाइन न होने के कारण सारा गंदा पानी सीधे यमुना में गिरता है।

उपायः दिल्ली सरकार को गंभीर होकर अपनी सारी नीतियों और योजनाओं पर अमल करना चाहिए। सारे रुके हुए प्रोजक्ट्स को सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। साथ ही आने वाले समय में बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए योजनाओं को बनाकर जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहिए। दिल्ली में सीवर लाइनों का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए तथा यमुना को प्रदूषित करने वालों पर सख्ती से भारी जुर्माना लगाना चाहिए।

आरोप नं.8– राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और केंद्र से लगातार तकरार

- मुख्यमंत्री को हमेशा दिल्ली के उप राज्यपाल से रही है तकलीफ
- अपने अहम के कारण लागू नहीं करना चाहते जनहित नीतियां
- पब्लिसिटी का है बेहद शौक
- स्टेटहुड के नाम पर अपनी नाकामी छुपाने का पुराना बहाना
- बिगड़ी कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों का ठीकरा फोड़ते हैं दिल्ली पुलिस पर

दिल्ली सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से काम न करने के कोई न कोई बहाने निकाल ही लेती है। कभी उप राज्यपाल से तकरार, कभी अफसरों से झगड़ा, कभी दिल्ली पुलिस पर दोष, कभी MCD पर इल्जाम, कभी बजट न होना(होगा भी कैसे जब 500 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में खर्च करने हैं) और इसी तरह के बेतुके कारण देकर जनहित कार्यों के अलावा सब कुछ कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में खतरनाक स्तर का प्रदूषण होने के बावजूद कभी ऑड–इवन का नाटक, कभी पड़ौसी राज्यों से बातचीत का दिखावा, कभी बेसरपैर की बैठकें और कभी अपनी कथित सही इरादों का बखान करते रहे।

उपायः मुख्यमंत्री जी को केवल एक ही सलाह है कि वह काम करें, जिसके लिये दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली के विकास और बेहतरी को अपना लक्ष्य बनाकर दिल्ली सरकार को दिन रात एक करके काम करना चाहिए। अगर अपना पूरा समय दूसरों की गलतियां निकालने में ही व्यतीत करेंगे, तो दिल्ली को एक सुनहरा शहर कैसे बना पाएंगे?

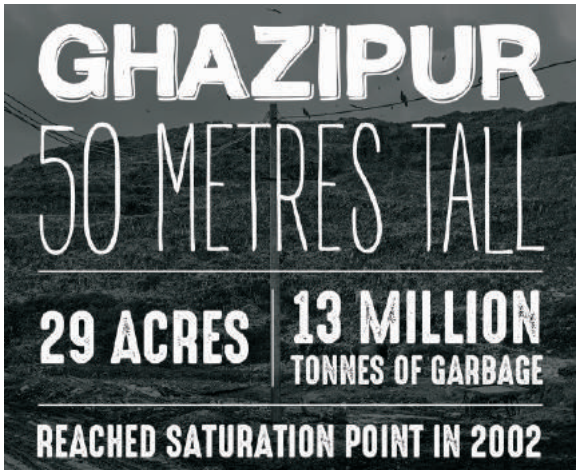

CHARGESHEET AGAINST
AAP GOVERNMENT IN DELHI

CHARGE NO. 1: AAP Government sits on Rs.829 Crore green fund

- **Rs 829 Crore Green tax** lying unutilized meant for augmenting public transport.
- While Delhi chokes, the AAP Government spent **only Rs 93 Lakhs** of the Green tax it collected as 'Environment compensation charge' from goods vehicles entering the city.
- Despite explicit directions from the Supreme Court, that all the the money collected from the cess levied on goods vehicles, the amount has not been spent on roads, public transport and cycle tracks.
- Further, another **Rs 500 Crore** collected as cess on every litre of diesel sold since 2008 is also lying unspent.
- Delhi's total bus fleet is **4000** as against a sanctioned strength of **11,000** as mandated by the **Delhi High Court.**
- With a total of 1260 Km of PWD roads, the AAP govt has **only 4** road cleaning machines whereas, an additional 10 machines are required.

CHARGE NO. 2: Odd Even Knee Jerk reaction will not solve air pollution knot

- Token Odd-Even vehicle rationing scheme will not bring down **toxic haze** in the capital city.
- The AAP government was dormant and procrastinated in taking emergency and immediate steps when the air pollution engulfed the city. After it reached the peak, the AAP government thought of implementing odd-even formula.
- Grand exemptions were proposed by the Delhi Government which naturally defeat the very purpose of the scheme. The Two wheelers were proposed to be exempted which constitute 65% of the vehicles registered in Delhi. Studies show that 4 wheelers in Delhi account for just 10% of the vehicular pollution.
- Even the **National Green Tribunal (NGT)** was not happy about the design of the scheme and hence naturally after its verdict, the AAP Government withdrew the scheme mainly taking into account the vote bank.
- Earlier analysis of the Odd-even scheme implemented earlier showed that instead of bringing down the number of vehicles on the road, it proved as a boon to 2nd hand car dealers as their sales went up exponentially. This bizarre response from the people was in anticipation that this erratic Government will implement the odd-even scheme whimsically in future also.
- Ad hocism on the part of the AAP government with one or two measures would not solve the pollution crisis in the capital, instead a comprehensive plan and long term measures are needed to improve the air quality.
- It is well known that the Odd even formula was implemented last time mainly by the AAP Government for publicity, sensationalism and stunt. It was indeed done to create an atmosphere of ballooning the radical image of Kejriwal as a hero, a saviour and a messiah of Delhi.
- When the brainless idea of Odd-even was implemented last time in the month of April,2016 , it resulted in creating massive constraint on the public transport system in Delhi which was not envisaged to cater to such a large number of people. The iconic Delhi Metro was choked to the hilt in commuting passengers as it did not have the necessary wherewithal to deal with such a war like situation. Therefore, the execution of the scheme was ill-conceived.
- Just to satisfy one man's ego, 1.3 Crore people were subjected toundue hardships and were left on the road cursing the Odd-even scheme.

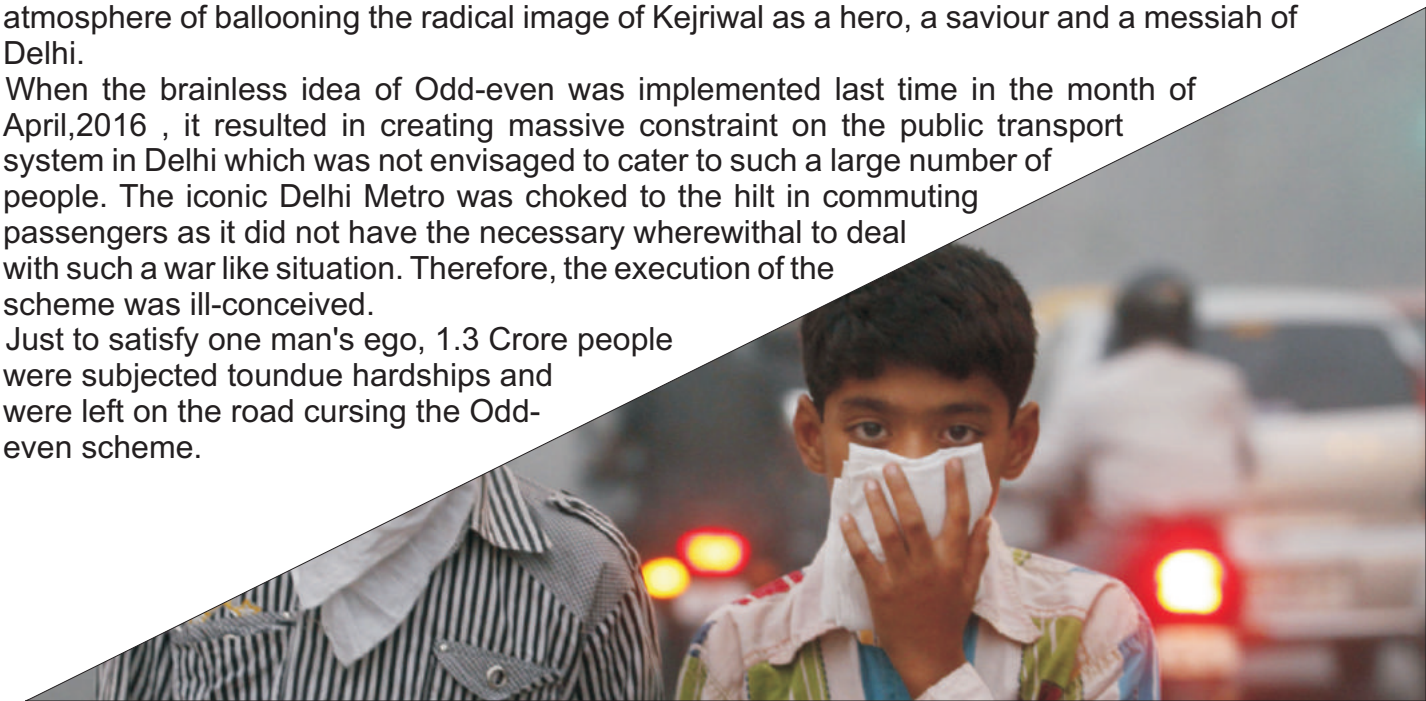

CHARGE NO.3: Stubble burning in the nearby States needs practical solutions

- The AAP was indeed in an imaginary world for almost 3 years of its capricious and impulsive rule and did not initiate any practical measures on the issue of stubble burning.
- The AAP government did not realize that the major cause of Delhi's air pollution is stubble burning in the near by States and the road dust. On both these issues, the Delhi government has miserably failed, thus forcing the people of Delhi to breathe poisonous and venomous air at the cost of their lives.
- In 3 years of its misrule, the Delhi Government did not even care to discuss even once with the Governments of Haryana, Punjab, and Rajasthan on the vexatious issue of stubble burning. When the poisonous air mass engulfed the capital, then only the AAP government thought of interacting with the neighbouring States.
- The AAP government with its petty animosity with the Central Government, did not think of discussing the alarming issue of air pollution with the concerned authorities such as Central Pollution Control Board (Ministry of Environment and Forests), ICAR (Indian Council of Agricultural Research), CSIR (Council for Scientific and Industrial Research). The Delhi Government kept its personal and political interests over public good.

CHARGE NO.4: Dusty Roads, Dusty Government

- The AAP Government does not realize that the major culprit (50%) behind Delhi's Air Pollution is the Road Dust emanating from open patches, soil, open dump sites, industrial emissions and construction activity.
- The Delhi Government has been sleeping without initiating any new measures to curtail the circulation of road dust. No additional vegetation has been planted on the roads, central verge and highways.
- It is a situation of utter disgrace that despite the **Supreme Court** direction, vacuum cleaning of roads and repair of pavements in the national capital have not been undertaken.
- The Delhi Government in its selfish and cheap political interest, did not act upon curbing the rampant and unbridled unauthorized and illegal construction activities which in turn perpetuated the circulation of road dust.
- Open landfills, which are a big source of dust, however the Delhi Government in all its ignorance did not create a system of technology driven solid waste management.
- The City Government did not have a plan in place for sprinkling of water, Cloud Seeding and Multi Function Dust Separation to curb dust dissemination.

CHARGE NO.5 : Unhindered industrial pollution and construction emissions

- Smoke guzzling industrial establishments have been mushrooming throughout the whole city, in violation of extant Acts, rules, orders and instructions, right beneath the nose of the city government.
- There is absolutely no system in place to check construction of unauthorized warehouses, industries and residential structures.
- The Licensing system for establishing manufacturing units is in utter shambles.
- Emissions from Industrial units are the 2nd major reason for air pollution in Delhi.

CHARGE NO.6: Uncontrolled and explosive maze of waste at land fill sites

- Delhi Government did not have the time in 3 years to find a solution to the Bhalaswa, Okhla and Ghazipur land fill sites.
- The open land fill sites have become monstrous and are disaster sites looming for catastrophe to happen.
- There has been absolutely no thought of the Delhi Government in creating new STPs- Sewage Treatment Plants and their effective rollout for the increasing populace.

CHARGE NO.7: Dying Yamuna

- 18 Sewers join in the 22 km stretch of river Yamuna in Delhi
- Untreated industrial waste and chemical pollution are the biggest challenges
- The biggest fact is that the river Yamuna has no biological oxygen left.
- The AAP government in its effort to please its vote bank organizes Yamuna Arti, however no steps have been initiated for its cleaning.
- It is surprising that Levels of ammonia have increased to 1.8 ppm(parts per million) in the river, still it does not ring the alarm bells for the Delhi Government.

CHARGE NO. 8 : Melodrama of tussles with the central government is a way of life

- The Delhi Chief Minister cannot sleep if he does not criticize the LG on day to day basis.
- The AAP government in its ego is not letting the benefits of Central Government Schemes to trickle down to the residents of Delhi.
- The AAP Government is fond of cheap theatrics and media publicity.
- In the garb of Statehood, the Delhi Government always tries to hide its non-performance and non-governance.

Delhi's air pollution rises 23% during second odd-even phase

Data indicate that the scheme cannot work in the long term without additional actions, such as improving bus services, curbing factory and truck emissions

वायु प्रदूषण कम करने में नाकाम रहा है ऑड-इवेन

ऑड-इवन के नाम पर ड्रामा कर रही है सरकार

सांध्य टाइम्स | Updated: Nov 10, 2017, 12:26PM IST

अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऑड-ईवन से पीछे हटी केजरीवाल सरकार

क्या महिलाओं के फेफड़े ज्यादा मजबूत होते हैं जो उन्हें ऑड-ईवन से छूट मिलती है